outs were charged to the revenue of the year. They were unfunded. In 1981, an internal audit showed that the provision meant for the pension fund was short by Rs. 203 crores. Actuaries suggested that the Railways make regular provisions for the pension fund liabilities, but the advice was not heeded. If the present trend continues, the Indian Railways face the prospect of having to pay out almost half of its gross traffic receipts as pensions to its retirees by 2020.

I urge upon the Central Government to enlighten the House about the present quantum of pension liabilities of the Railways and the remedial measures planned. Thank you.

Demand from provision of Fire fighting system in the Rural Areas of the Country

श्री पी. के. माहेश्वरी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयत्नों की ओर दिलाना चाहता हूँ। भारत कृषि प्रधान देश है। अप्रैल और मई महीने में फसलें खेत से लेकर खलिहानों तक फैली रहती हैं। इस मौसम में तेज गर्म हवायें या अंधड़ भी चलते रहते हैं। इसी मौसम में फसलें पक कर तैयार होती हैं। इन तैयार फसलों में कृषि उपकरणों से निकली चिंगारी या लापरवाही से आग लगने का खतरा बना रहता है। देश भर में इसी मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने की सैकड़ों घटनाएं होती रहती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जन, धन एवम् अनाज की क्षति होती है।

महोदया, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब होती है, जब सुदूरवर्ती गावों में धू-धू कर जल रही फसलें व गांव कई दिनों तक जलते रहते हैं, लेकिन उनके बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती क्योंकि शहरों या कस्बों में ही अग्निशमन की समुचित व्यवस्था नहीं रहती। बेचारा किसान अपनी किस्मत को रोता रह जाता है। विडंबना यह है कि संचार क्रांति के बावजूद गांवों की सूचना शहरों तक आने में घंटों या कभी-कभी कई दिन बीत जाते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को आग बुझाने वाले उपकरणों व दमकलों की खरीद के लिए केन्द्रीय सहायता या रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराए, जिससे किसान अपनी मेहनत की वर्ष भर की कमाई को बचा सके। गांवों में आग बुझाने की व्यवस्था का जरूरी काम बदहाल आर्थिक स्थिति वाले राज्यों पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए केन्द्र सरकार इस मामले में स्वयं ठोस पहल करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बालकवि बैरागी : महोदया, मैं अपने को इससे संबद्ध करता हूँ।